

**Bureau of Indian Standards
Public Relations Department**



FOR IMMEDIATE RELEASE

Ref No: PRD/Press Note/05/2024-25

Date: 23/07/2024

BIS Accelerates R&D Efforts for Emerging Domains

**82 Projects with Top Scientific Institutes Sanctioned to Boost Advanced
Standardisation Efforts**

New Delhi – The Bureau of Indian Standards (BIS), as the National Standards Body of India, continues to spearhead the development of Indian Standards for products, processes, and services. To date, BIS has formulated more than 22,000 Indian Standards, playing a crucial role in ensuring the quality and safety of a wide array of goods and services in the country. Recognising the vital importance of Research & Development (R&D) in the standardisation process, BIS is intensifying its efforts to address the challenges posed by rapid technological advancements and the transformative changes in business and social spheres.

In response to the increasing diversification, innovation, and complexities in the manufacturing sector and the evolution of services, BIS has emphasised the need to integrate R&D projects into the standardisation process. This integration requires leveraging an extensive network of domain experts capable of conducting thorough research and development work. To expand the existing network, BIS has entered into Memorandums of Understanding (MoUs) with premier educational institutions, including IITs and NITs, thereby tapping into the vast intellectual capital available with their faculty and research scholars.

Through these MoUs, BIS aims to promote research and development necessary for standards formulation while simultaneously supporting the research ecosystem within these educational institutions. This strategic partnership facilitates a comprehensive approach to R&D, encompassing focus group discussions on chosen subjects for standardisation, and detailed field-level studies of current processes and practices in product manufacturing and service delivery.

BIS has recently sanctioned 82 R&D projects to faculty members of various prominent technical institutes, including IITs, NITs, and other experts, to expand further, diversify, and accelerate research and development activity. These projects, each with a budget of up to ten lakh rupees and a completion timeline of six months, are not confined to theoretical reviews but involve extensive field-level studies. The focus areas of these projects include cutting-edge domains such as:

- Artificial Intelligence,
- Blockchain Technology,
- Medical Devices,
- Renewable Energy,

- Sustainability,
- Smart cities,
- Digital Transformation.

By addressing these emerging areas, BIS aims to develop standards that safeguard consumers and ensure the quality and reliability of innovative products and services.

In addition to the 82 sanctioned projects, 99 more are in the allotment process, with another 66 projects available for application. These opportunities can be accessed through the BIS website at [BIS R&D Projects](#). This initiative enhances the standardisation process and substantially supports the research community, fostering an environment of innovation and excellence in academic institutions across India.

Shri Pramod Kumar Tiwari, Director General, BIS, highlighted the significance of these efforts and stated, "Our collaboration with premier educational institutions and the sanctioning of numerous R&D projects signify our commitment to advancing the standardisation process in line with technological advancements and evolving industry needs. With the enhanced focus on research and development in our standards formulation process, we aim to ensure that our standards are robust, relevant, and capable of addressing the challenges of modern technology and industry practices."

The Bureau of Indian Standards (BIS) remains dedicated to developing comprehensive, up-to-date standards that reflect the latest technological trends and industry practices. Through these enhanced R&D efforts, BIS seeks to safeguard consumer interests and contribute to developing a safer, more reliable marketplace in India.

For more information about BIS's R&D initiatives and to explore available projects, the BIS website, i.e. www.bis.gov.in, may be visited.

भारतीय मानक ब्यूरो जनसंपर्क विभाग



तत्काल प्रकाशन हेतु

संदर्भ संख्या: पीआरडी/प्रेस नोट/05/2024-25

दिनांक : 23/07/2024

बीआईएस द्वारा नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में गति प्रदान की गई

उन्नत मानकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वैज्ञानिक संस्थानों के साथ 82 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

नई दिल्ली – भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानकों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज तक, BIS ने 22,000 से अधिक भारतीय मानक तैयार किए हैं, जो देश में वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मानकीकरण प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास (R&D) के महत्व को पहचानते हुए तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलावों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने प्रयासों में गति ला रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती विविधता, नवाचार और जटिलताओं तथा सेवाओं के विकास को देखते हुए बीआईएस ने मानकीकरण प्रक्रिया में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया है। इस एकीकरण के लिए गहन अनुसंधान और विकास कार्य करने में सक्षम डोमेन विशेषज्ञों के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाने की आवश्यकता है। मौजूदा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए बीआईएस ने आईआईटी और एनआईटी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उनके संकाय और शोध विद्वानों के पास उपलब्ध विशाल बौद्धिक पूंजी का लाभ उठाया जा सके।

इन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के माध्यम से बीआईएस का लक्ष्य मानकों के निर्माण के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है एवं साथ ही साथ इन शैक्षणिक संस्थानों के भीतर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करना है। यह रणनीतिक साझेदारी अनुसंधान और विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें मानकीकरण के लिए चुने गए विषयों पर विषय केन्द्रित समूह चर्चा और उत्पाद निर्माण और सेवा वितरण में वर्तमान प्रक्रियाओं और रीतियों के विस्तृत क्षेत्र-स्तरीय अध्ययन शामिल हैं।

बीआईएस ने हाल ही में आईआईटी एनआईटी और अन्य विशेषज्ञों सहित विभिन्न प्रमुख तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों को अनुसंधान और विकास गतिविधि को आगे बढ़ाने, विविधता लाने और गति देने के लिए 82 आरएंडडी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएँ जिनमें से प्रत्येक का बजट दस लाख रुपये तक है और छह महीने में पूरी होने की समयसीमा है तथा ये केवल सैद्धांतिक समीक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें व्यापक क्षेत्र-स्तरीय अध्ययन शामिल हैं। इन परियोजनाओं के फोकस क्षेत्रों में अत्याधुनिक डोमेन शामिल हैं जैसे:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
- ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी,
- चिकित्सा उपकरण ,
- नवीकरणीय ऊर्जा,
- सततता ,
- स्मार्ट शहर,
- डिजिटल परिवर्तन।

इन उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देकर बीआईएस का लक्ष्य ऐसे मानक विकसित करना है जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा करें तथा नवोन्मेषी उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करें।

82 स्वीकृत परियोजनाओं के अलावा 99 और परियोजनाएं आवंटन प्रक्रिया में हैं तथा 66 अन्य परियोजनाएं आवेदन के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रयोजनाओं की विस्तृत जानकारी बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध [बीआईएस आरएनडी प्रोजेक्ट्स](#) पर देखी जा सकती है। यह पहल मानकीकरण प्रक्रिया में बढ़ोतरी करती है तथा अनुसंधान समुदाय को पर्याप्त रूप से सहायता प्रदान करती है, जिससे पूरे भारत के शैक्षणिक संस्थानों में नवोन्मेष और उत्कृष्टता का परिवेश बनता है।

बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने इन प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, "प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ हमारा सहयोग और कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी देना तकनीकी प्रगति और उभरती हुई उद्योग अपेक्षाओं के अनुरूप मानकीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मानक निर्माण प्रक्रिया में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे मानक सशक्त एवं प्रासंगिक हों और आधुनिक प्रौद्योगिकी और उद्योग रीतियों की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हों।"

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) व्यापक, अद्यतन मानकों को विकसित करने के लिए समर्पित है जो नवीनतम तकनीकी रुझानों और उद्योग रीतियों को दर्शाते हैं। इन उन्नत अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से बीआईएस उपभोक्ता हितों की रक्षा करना चाहता है और इस प्रकार भारत में एक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बाज़ार विकसित करने में योगदान देना चाहता है।

बीआईएस की अनुसंधान एवं विकास पहलों के बारे में अधिक जानकारी के लिए तथा उपलब्ध परियोजनाओं की जानकारी के लिए बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in देखी जा सकती है।